AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

मनरेगा का लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर प्रभावः उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के हनुमानगंज एवं दुबहड़ विकास खंड का एक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
अभिषेक चतुर्वेदी
सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
गंगा सिंह महाविद्यालय (जय प्रकाश विश्वविद्यालय)
छपरा, सारण, बिहार, भारत

शोध सार

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के हनुमानगंज एवं दुबहड़ विकास खंड में मनरेगा लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें 100 लाभार्थियों का चयन बहु–स्तरीय नमूना पद्धति के माध्यम से किया गया। सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आंकलन आय, रोजगार स्थिरता, आवास, उपभोग स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यय जैसे संकेतकों पर आधारित सामाजिक–आर्थिक सूचकांक (SES) के माध्यम से किया गया। अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा के पश्चात् औसत SES स्कोर 1.48 से बढ़कर 2. 30 हो गया, जो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया ($t = 4.12$, $p < 0.05$)। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा, उपभोग क्षमता एवं जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक रही है।

मुख्य शब्द

मनरेगा, सामाजिक–आर्थिक स्तर, ग्रामीण रोजगार, बलिया, SES सूचकांक.

भूमिका

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था लंबे समय से गरीबी, बेरोजगारी एवं आय–अस्थिरता जैसी संरचनात्मक समस्याओं से जूझती रही है। विशेष रूप से कृषि पर निर्भर क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेरोजगारी व्यापक रूप से पाई जाती है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ग्रामीण परिवारों के लिए आय–सुरक्षा प्रदान करने वाले एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया।

मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन करना है। यह योजना न केवल रोजगार सृजन का माध्यम है, बल्कि ग्रामीण जीवन–स्तर में सुधार, उपभोग क्षमता में वृद्धि तथा सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस अध्ययन में बलिया जनपद के चयनित विकास खंडों में मनरेगा के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- मनरेगा लाभार्थियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का आंकलन करना।
- मनरेगा के पूर्व एवं पश्चात सामाजिक–आर्थिक स्तर में परिवर्तन का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण परिवारों की आय–सुरक्षा एवं जीवन–स्तर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना

शून्य परिकल्पना (H_0): मनरेगा का लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1): मनरेगा का लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

शोध प्रविधि

यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया। बहु–स्तरीय नमूना पद्धति के माध्यम से बलिया जनपद के हनुमानगंज एवं दुबहड़ विकास खंड से कुल 100 लाभार्थियों का चयन किया गया।

सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आंकलन हेतु एक संयुक्त सूचकांक (SES Index) तैयार किया गया, जिसमें निम्न संकेतकों को शामिल किया गया:

- आय स्तर।
- रोजगार के दिनों की संख्या।
- आवास की स्थिति।
- उपभोग व्यय।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय।
- परिसंपत्ति स्वामित्व।

विश्लेषण के लिए औसत (Mean) तथा t–test का उपयोग किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के दो विकास खंडों हनुमानगंज एवं दुबहड़ पर आधारित है। यह क्षेत्र कृषि–प्रधान है तथा यहाँ सीमांत एवं भूमिहीन परिवारों की संख्या अधिक है। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण मनरेगा यहाँ आय–सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

परिणाम एवं विश्लेषण

तालिका 1: मनरेगा के पूर्व एवं पश्चात औसत सामाजिक–आर्थिक स्तर की तुलना (N = 100)

अवधि	औसत SES स्कोर	N
मनरेगा से पूर्व	1.48	100
मनरेगा के पश्चात्	2.30	100

*(**स्रोत**: प्राथमिक समंक)*

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के पश्चात लाभार्थियों के औसत सामाजिक–आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। t–test का मान 4.12 प्राप्त हुआ, जो 5 प्रतिशत स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है ($p < 0.05$)।

यह परिणाम दर्शाता है कि योजना ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला हैः

- आय–सुरक्षा में वृद्धि।
- खाद्य एवं उपभोग क्षमता में सुधार।
- आवास की स्थिति में सुधार।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि।

अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

चर्चा

अध्ययन के निष्कर्ष यह संकेत करते हैं कि मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए आय–स्थिरीकरण का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। नियमित मजदूरी उपलब्ध होने से परिवारों की उपभोग क्षमता बढ़ी है तथा ऋण पर निर्भरता में कमी आई है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक–आर्थिक सुधार का प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन–स्तर जैसे मानवीय विकास संकेतकों पर भी देखा गया। यह अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) के अनुरूप है, जिसके अनुसार आय में वृद्धि व्यक्ति की जीवन–क्षमता एवं विकल्पों का विस्तार करती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा ने अध्ययन क्षेत्र में लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक स्तर में महत्वपूर्ण सुधार किया है। योजना ने ग्रामीण परिवारों को आय–सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाने में भी योगदान दिया है।

इस प्रकार मनरेगा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन सिद्ध होती है।

सुझाव

- रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए।
- समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- स्थायी परिसंपत्ति निर्माण पर अधिक ध्यान दिया जाए।
- महिला सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए।
- योजना की निगरानी एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ किया जाए।

संदर्भ सूची

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2014–2023) मनरेगाः वार्षिक प्रतिवेदन (विभिन्न वर्ष). नई दिल्ली।
2. नीति आयोग, (2015–2023) विभिन्न रिपोर्ट एवं दस्तावेज. भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अमर्त्य सेन (1999) Development as Freedom, Oxford University Press, Noida.
4. विश्व बैंक (2014–2023). World Development Report (Various Issues). Washington, D.C.
5. Dutt, R. & Sundaram, K.P.M. (2022) Indian Economy. S. Chand & Company Ltd, New Delhi.
6. चतुर्वेदी ए. (2024) 2014 के पश्चात् मनरेगा का ग्रामीण क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, अप्रकाशित पी–एच.डी. शोध प्रबंध, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ.प्र.)।

––==00==––